19th Year
Issue: 196
18.11.2025 (TUESDAY)
ROURKELA
R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
(Pages-6)
Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar
प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल
Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्री बस हादसा, पीएम मोदी ने जताया दुख, परिवारों के साथ संवेदनाएं

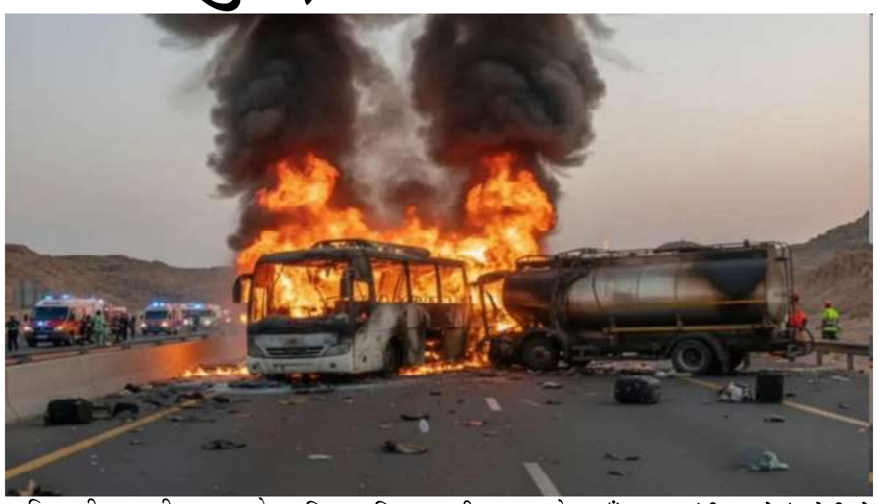

नयी दिल्ली १७/११ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने ङ्ग पर एक पोस्ट में कहा कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वह इस घटना से गहरा सदमा महसूस कर रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास सभी प्रभावित परिवारों को पूर्ण सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा लगा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूर्ण सहायता प्रदान कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। मु यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है, क्योंकि रिपोर्टों में बताया गया है कि कई पीड़ित हैदराबाद से थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मु यमंत्री ने नई दिल्ली में अधिकारियों से संपर्क किया है और उन्हें नवीनतम जानकारी के लिए रियाद स्थित भारतीय दूतावास के साथ निकट समन्वय करने का निर्देश दिया है। सोमवार को मदीना के पास श्रद्धालुओं से भरी एक यात्री बस के डीजल टैंकर से टकरा जाने से कम से कम 45 उमराह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। यह बस भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों को मक्का से मदीना ले जा रही थी और यह दुर्घटना सोमवार तड़के लगभग 1=30 बजे हुई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, ज़्यादातर तीर्थयात्री हैदराबाद के थे। तीर्थयात्री मक्का में अपने पवित्र अनुष्ठान पूरे करने के बाद मदीना लौट रहे थे। दुर्घटना के समय सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। मृतकों में हैदराबाद की 20 महिलाएँ और 11 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। बचाव अभियान जारी है और स्थानीय निवासी टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों की मदद के लिए घटनास्थल पर पहुँच गए हैं।

शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा

नयी दिल्ली १७/११ (संवाददाता): बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 (आईसीआर-1) ने जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई। आईसीटी ने हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराया और महीनों तक चले मुकदमे का समापन किया, जिसमें उन्हें पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले एक विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया था। आईसीटी का कहना है कि अशांति के दौरान 1,400 लोग मारे गए और 24,000 घायल हुए। आईसीटी जज ने कहा कि जुलाई-अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1,400 लोग मारे गए और लगभग 24,000 घायल हुए। जज ने यह भी कहा कि शेख हसीना की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए आग्नेयास्त्रों और हेलीकॉप्टरों सहित घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक हिंसा और तबाही हुई। आईसीटी के एक जज ने हसीना और दक्षिण ढाका नगर निगम के पूर्व मेयर के बीच कथित बातचीत को पढ़ते हुए कहा कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए हेलीकॉप्टरों और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया था।

आईसीटी जज ने यह भी कहा कि शेख हसीना ने रज़ाकार टिप्पणी करके हिंसा भड़काई और लोगों को देश का दुश्मन करार दिया। बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त आधार हैं। अदालत ने छात्रों की हत्या के लिए कथित तौर पर हिंसा भड़काने और 14 जुलाई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अपमानजनक टिप्पणियों का भी हवाला दिया।

हसीना उसी दिन बढ़ती अशांति के बीच बांग्लादेश छोड़कर भाग गईं और तब से भारत में रह रही हैं।

दोहरे पैन कार्ड मामले में आजम खान-अब्दुल्ला को 7 साल की जेल, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

लखनऊ १७/११ (संवाददाता): समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक विशेष सांसद-विधायक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोहरे पैन कार्ड मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है। खान और उनके बेटे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता आकाश सक्सेना ने दिसंबर 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में, सक्सेना ने आरोप लगाया कि दोनों के पास अलग-अलग जन्मतिथि वाले दोहरे पैन कार्ड थे।

सक्सेना ने आरोप लगाया कि खान और उनके बेटे ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके दो पैन कार्ड प्राप्त किए थे और उनका उपयोग बैंकिंग लेनदेन और आयकर विवरण के लिए कर रहे थे। दोषसिद्धि के बाद, आज़म खान और अब्दुल्ला दोनों को अदालत कक्ष में ही हिरासत में ले लिया गया। जल्द ही सज़ा सुनाई जाने की उ मीद है। शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी आदेश सुनाए जाने के समय मौजूद थे। आकाश सक्सेना द्वारा अब्दुल्ला आज़म पर अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग करके दो पैन कार्ड प्राप्त करने का आरोप लगाने के बाद 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, ये पैन कार्ड गलत और जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए थे और कथित तौर पर बैंकिंग, आयकर रिकॉर्ड और चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर, 1990 दर्ज थी।

बिहार में नई सरकार का रास्ता साफ, नीतीश 20 को लेंगे शपथ

पटना १७/११ (संवाददाता): हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा भारी जीत दर्ज करने के बाद अगले तीन से चार दिनों में नई बिहार सरकार का गठन हो जाएगा। सोमवार को एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद, मु यमंत्री नीतीश कुमार को मौजूदा विधानसभा भंग करने की सिफ़ारिश करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल आरिफ़ मोह मद ख़ान को अपना इस्तीफ़ा सौंपा।

सूत्रों ने सोमवार को बताया कि बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना में होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित एनडीए के कई अन्य शीर्ष नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उ मीद है। इससे पहले, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि नवनिर्वाचित विधायक मंगलवार को अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि संभवत: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 या 21 नवंबर को होगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना के गांधी मैदान में तैयारियाँ चल रही हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और राघोपुर से नवनिर्वाचित विधायक तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। पटना स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर राजद विधायकों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। यह बैठक बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, जहाँ गठबंधन को एनडीए से करारी हार का सामना करना पड़ा था। एनडीए ने बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 202 सीटें हासिल कीं, जबकि महागठबंधन को केवल 35 सीटें मिलीं, जबकि राजद को केवल 25 सीटें मिलीं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री एवं जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने बताया कि बैठक के बाद मु यमंत्री ने उपमु यमंत्री सम्राट चौधरी और मु य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ राज्यपाल आरिफ मोह मद खान से मुलाकात कर कैबिनेट के निर्णय से उन्हें अवगत कराया। विजय चौधरी ने कहा, कैबिनेट ने नयी सरकार के गठन के मद्देनजर 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा करने का प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट ने राजग की ऐतिहासिक जीत के लिए मु यमंत्री को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पारित किया। चौधरी ने कहा, यह नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है जो राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों के कारण संभव हुआ है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में 243 सदस्यीय सदन में राजग ने 200 से अधिक सीट पर जीत दर्ज की है, जिनमें भाजपा ने सर्वाधिक 89 सीट जीतीं और जनता दल (यूनाइटेड) को 85 सीट मिलीं। जद(यू) के एक सूत्र ने बताया कि पार्टी 19 नवंबर को नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुनेगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को यहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनके आवास पर अलग-अलग बैठक की।

नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ा, बिहार में एनडीए की सरकार बनने की तैयारी तेज

पटना १७/११ (संवाददाता): बिहार के मु यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोह मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिससे हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में गठबंधन की व्यापक जीत के बाद नई एनडीए सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। कुमार का यह कदम निवर्तमान कैबिनेट की बैठक के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्हें सरकार गठन के लिए 卐ावश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस इस्तीफे के साथ ही एनडीए समर्थित नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 200 से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। भाजपा 89 सीटों के साथ शीर्ष पर है, जबकि जेडी(यू) 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। मु य निर्वाचन अधिकारी ने इससे पहले निर्वाचित सदस्यों की सूची राज्यपाल को सौंप दी थी, जिससे सत्ता परिवर्तन के लिए एक और प्रक्रियात्मक कदम आगे बढ़ गया। जेडी(यू) के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। संकेत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वह नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में ज़रूर शामिल होंगे। भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी ने %विकसित बिहार की नींव रखी है और जब पीएम मोदी बिहार के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे.

निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया

नयी दिल्ली १७/११ (संवाददाता): निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का सोमवार को आदेश दिया। असम के मु य निर्वाचन अधिकारी के लिए चुनाव प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, एक जनवरी, 2026 राज्य के लिए विशेष संशोधन करने की पात्रता तिथि होगी।

अधिकारियों के अनुसार, विशेष पुनरीक्षण, मतदाता सूचियों के वार्षिक विशेष सारांश पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच की प्रक्रिया है। आयोग ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एसआईआर का पिछले महीने आदेश दिया था। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। असम के लिए एसआईआर की घोषणा अलग से की गई है, जहां 2026 में चुनाव होने हैं।

एससी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल न करने के पक्ष में हैं गवई

नयी दिल्ली १७/११ (संवाददाता): भारत के मु य न्यायाधीश बीआर गवई ने पुष्टि की कि वह अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल न करने के पक्ष में हैं। चीफ जस्टिस बीआर. गवई ने दोहराया कि वह अनुसूचित जातियों (एससी) के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल न करने के पक्ष में हैं। गवई ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण के मामले में एक आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना एक गरीब खेतिहर मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती। गवई ने कहा, मैंने आगे बढ़कर यह विचार रखा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू होनी चाहिए। जो अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है, वही एससी पर भी लागू होना चाहिए, हालांकि इस मसले पर मेरी व्यापक रूप से आलोचना हुई है।

मु य न्यायाधीश ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में समानता या महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया तेज़ हो रही है और उनके साथ होने वाले भेदभाव की कड़ी आलोचना की गई है। उन्होंने कहा कि मु य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले, उन्होंने जो आखिरी समारोह में भाग लिया था, वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में था, जबकि मु य न्यायाधीश बनने के बाद उनका पहला समारोह महाराष्ट्र के अमरावती में था। न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए।

यह कहते हुए कि भारतीय संविधान स्थिर नहीं है, न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि डॉ. बीआर अंबेडकर हमेशा मानते थे कि इसे विकसित, जैविक और एक अत्याधुनिक जीवंत दस्तावेज़ होना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है।

विविध समाचार

बिहार में करारी हार के बाद तेजस्वी बने नेता प्रतिपक्ष

पटना १७/११ (संवाददाता): राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और राघोपुर से नवनिर्वाचित विधायक तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। पटना स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर राजद विधायकों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। यह बैठक बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, जहाँ गठबंधन को एनडीए से करारी हार का सामना करना पड़ा था। एनडीए ने बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 202 सीटें हासिल कीं, जबकि महागठबंधन को केवल 35 सीटें मिलीं, जबकि राजद को केवल 25 सीटें मिलीं।

तेजस्वी के करीबी सहयोगी संजय यादव जिन्हें लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए ज़ि मेदार ठहराया है भी बैठक में मौजूद थे। गहन चर्चा के बाद, हार का कारण ईवीएम हैकिंग और चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया बताया गया। रोहिणी आचार्य के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, जिन्होंने हाल ही में अपने परिवार से संबंध तोड़ लिए थे और तेजस्वी तथा उनके करीबी सहयोगियों पर उन्हें गाली-गलौज करने तथा घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था।

रविवार को एक्स पर साझा की गई कई भावुक पोस्ट में, रोहिणी आचार्य ने कहा कि अपने पिता को गंदी किडनी देने के लिए वह शापित हैं। उन्होंने दावा किया कि अब वह अनाथ महसूस कर रही हैं। 47 वर्षीय आचार्य ने विवाहित महिलाओं को सलाह दी कि अगर परिवार में बेटा है तो अपने पिता के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उ मीद है कि कोई भी परिवार अपनी बेटी को वह सब सहते हुए नहीं देखेगा जो उन्होंने झेला है। उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद आई है।

उन्होंने हाल ही में हुए बिहार चुनावों में पार्टी की करारी हार के लिए अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके दो करीबी सहयोगियों - राजद सांसद संजय यादव और रमीज को जि मेदार ठहराया।

बिहार में पुरानी विधानसभा भंग, नीतीश के नेतृत्व को सलाम; अब नई सरकार का इंतजार

पटना १७/११ (संवाददाता): जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) नेता विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को घोषणा की कि बिहार मंत्रिमंडल ने 19 नवंबर से प्रभावी रूप से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की औपचारिक सिफारिश कर दी है।

यह निर्णय आज दिन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। यह सिफारिश मु यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से बिहार के राज्यपाल आरिफ मोह मद खान को भेज दी गई है। इससे पहले, नीतीश कुमार ने पटना स्थित राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की शानदार जीत और नई सरकार के संभावित गठन के बाद सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।घटनाक्रम की जानकारी देते हुए चौधरी ने पत्रकारों को बताया आज कैबिनेट की बैठक हुई।

कैबिनेट ने 19 नवंबर से मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफ़ारिश की है। यह बात मु यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को बता दी गई है। कैबिनेट ने दो अतिरिक्त प्रस्ताव भी पारित किए।

दूसरे प्रस्ताव में मौजूदा सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार भर के सरकारी अधिकारियों के सहयोग के लिए उनकी सराहना की गई। चौधरी ने कहा कि दूसरा प्रस्ताव यह था कि वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन और क्रियान्वयन किया है। इसके लिए मु य सचिव सहित बिहार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की सराहना की गई है। तीसरे प्रस्ताव में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में एनडीए की प्रचंड जीत को स्वीकार करते हुए मु यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा की गई।जदयू नेता ने आगे कहा, तीसरा प्रस्ताव यह था कि हाल ही में संपन्न आम चुनावों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने जबरदस्त सफलता हासिल की और प्रचंड बहुमत हासिल किया। मंत्रिपरिषद ने मु यमंत्री को बधाई दी और उनके नेतृत्व में एनडीए के सफलता के शिखर पर पहुँचने के लिए आभार व्यक्त किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खिलाफ भाजपा का बड़ा एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित

नयी दिल्ली १७/११ (संवाददाता): बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है। यह कदम राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के एक दिन बाद उठाया गया है। बिहार के आरा से पूर्व सांसद सिंह एनडीए नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे और राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रहे थे। भाजपा ने आज सुबह सिंह को भेजे एक नोटिस में कहा कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। यह अनुशासन के दायरे में आता है। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। इसलिए, निर्देशानुसार, आपको पार्टी से निलंबित किया जा रहा है और यह बताने के लिए कहा गया है कि आपको पार्टी से क्यों न निष्कासित कर दिया जाए। इसलिए, कृपया यह पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। पूर्व राजनयिक, सिंह मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गृह सचिव रह चुके हैं। वे 2013 में भाजपा में शामिल हुए और 2014 और 2019 में आरा से दो बार सांसद चुने गए। 2017 में, उन्हें मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री बनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे अपनी सीट हार गए। आपको बता दें कि चुनावी राज्य बिहार में, पहले चरण के मतदान से कुछ ही दिन पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया था। आरके सिंह ने राज्य में बिजली घोटाले का चौंकाने वाला खुलासा किया था। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया था कि राज्य के बिजली विभाग में 62,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मंत्रालय के कई अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं और उन्होंने इसकी केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच कराने की माँग की थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ नतीजों में से एक दर्ज किया और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को करारी हार दी। राजग की इस ऐतिहासिक जीत को 'ब्रैंड मोदी नीतीश' के रूप में देखा जा रहा है। इसके उलट, विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन 34 सीट पर सिमट गया। चुनाव परिणामों में राजग की जीत का फैलाव ऐसा था कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बिहार का चुनावी नक्शा हल्के हरे, केसरिया, जामुनी, नेवी ब्लू और सेरुलेन ब्लू रंगों से लगभग भर गया, जबकि 'इंडिया' गठबंधन के रंग सिर्फ छिटपुट रूप में दिखाई दिए। चुनाव नतीजों ने संकेत दिया कि मतदाताओं का भरोसा अब भी 'ब्रैंड नीतीश' पर कायम है। 2005 से अब तक विभिन्न चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने का उनका रिकॉर्ड जनता के विश्वास का केंद्र रहा।

नर्मदा में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी शक्ति को किया सलाम

नयी दिल्ली १७/११ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के नर्मदा ज़िले में एक रोड शो किया। यहाँ उपस्थित जनसमूह ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नर्मदा स्थित देवमोगरा मंदिर में पूजा-अर्चना की। इससे पहले, प्रधानमंत्री निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करने के लिए सूरत पहुँचे और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (एमएएचएसआर) की प्रगति की समीक्षा की। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में से एक है और देश के हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के युग में प्रवेश का प्रतीक है।

केंद्र सरकार देश के आदिवासी नायकों के पराक्रम और अमूल्य योगदान को स मानित करने के लिए पूरे भारत में जनजातीय गौरव वर्ष मना रही है। 15 नवंबर को, केंद्र ने नर्मदा ज़िले में राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाकर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई। प्रधानमंत्री ने आज आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और उपनिवेशवाद-विरोधी आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अद्वितीय योगदान के लिए आदिवासी नेता को याद किया।

उन्होंने कहा कि विदेशी शासन के अन्याय के विरुद्ध मुंडा का संघर्ष और बलिदान देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भी शुभकामनाएं दीं, जो बिरसा मुंडा की जयंती के साथ ही पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को आदिवासी संस्कृति से समृद्ध भूमि बताया और क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि की कामना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने %ङ्ग% पर लिखा कि जनजातीय गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर, पूरा देश मातृभूमि के गौरव की रक्षा में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी के अद्वितीय योगदान को श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। विदेशी शासन के अन्याय के विरुद्ध उनका संघर्ष और बलिदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी 150वीं जयंती पर शत-शत नमन।उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति से समृद्ध, गौरवशाली झारखंड राज्य के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती का इतिहास साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथाओं से भरा पड़ा है। आज इस विशेष अवसर पर, मैं राज्य में अपने सभी परिजनों के साथ राज्य की प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूँ।

मोदी का कांग्रेस पर हमला- 6 दशक तक की आदिवासियों की उपेक्षा, अब विकास हमारी प्राथमिकता

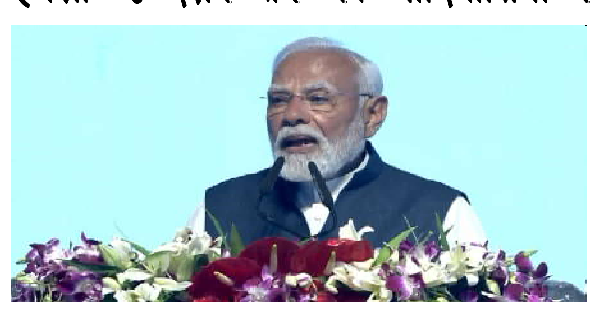

नयी दिल्ली १७/११ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी गौरव हज़ारों वर्षों से भारत की चेतना का अभिन्न अंग रहा है और देश स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समाज के योगदान को नहीं भूल सकता। जनजातीय गौरव दिवस पर यहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी गौरव हज़ारों वर्षों से भारत की चेतना का अभिन्न अंग रहा है। जब भी देश के स मान, स्वाभिमान और स्वशासन का प्रश्न उठा है... हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा रहा है। हम स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समाज के योगदान को नहीं भूल सकते।

मोदी ने कांग्रेस सरकारों पर अपने शासनकाल में आदिवासी समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छह दशकों तक कांग्रेस सरकारों ने आदिवासी समुदायों को उनके हाल पर छोड़ दिया। कुपोषण कायम रहा, शिक्षा दुर्लभ थी और ये कमियाँ कई आदिवासी क्षेत्रों की दुर्भाग्यपूर्ण पहचान बन गईं। कांग्रेस सरकारें उदासीन रहीं। भाजपा के लिए आदिवासी कल्याण हमेशा प्राथमिकता रही है। हम अपने आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां नर्मदा की ये पावन धरती आज एक और ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बन रही है। अभी 31 अक्टूबर को हमने यहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई। हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ है। और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की चर्चा होती है, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की चर्चा होती है, अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा होती है, केदारनाथ धाम की चर्चा होती है। पिछले एक दशक में ऐसे कई हमारे धार्मिक, ऐतिहासिक स्थानों का विकास हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2021 में हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब-जब देश के स मान स्वाभिमान और स्वराज की बात आई... तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भगवान बिरसा मुंडा को कोई याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल-बगल के गांव तक ही पूछा जाता था। आज देशभर में कई ट्राइबल यूजियम बनाए जा रहे हैं।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है, जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई-बहनों के साथ किया गया है। देश में छह दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चलें कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे।

छत्तीसगढ़ शासन जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए संकल्पित-विष्णुदेव साय

जगदलपुर १७/११ (संवाददाता): धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मु यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जगदलपुर के सिटी ग्राउंड में विभिन्न जनजातीय समाज के प्रमुखों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान मु यमंत्री का पारंपरिक सिहाड़ी माला, पगड़ी (साफा) और एक विशाल गजमाला भेंट कर स मान किया गया, जिसने पूरे आयोजन में सांस्कृतिक उल्लास भर दिया।

मु यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिटी ग्राउंड, जगदलपुर में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी और भगवान बिरसा मुंडा के छायाचित्र सहित जनजातीय देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना कर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात अपने उद्बोधन में मु यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

मु यमंत्री ने जनजातीय उत्थान और स मान के लिए उठाए गए ऐतिहासिक राष्ट्रीय कदमों का स्मरण करते हुए कहा कि जनजातीय कल्याण की दिशा में तीन बड़े मील के पत्थर रखे गए हैं।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को याद किया, जिनके कार्यकाल में ही आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का गठन किया गया। मु यमंत्री ने इसे जनजातीय पहचान को स मान देने और उनके त्वरित विकास की दिशा में युगांतरकारी निर्णय बताया। इसके अतिरिक्त, वाजपेयी जी ने ही जनजातीय हितों की रक्षा और विकास हेतु एक अलग 'जनजातीय कार्य मंत्रालय' का गठन किया। मु यमंत्री श्री साय ने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित कर पूरे राष्ट्र में जनजातीय नायकों के स मान की एक ऐतिहासिक परंपरा स्थापित की। मु यमंत्री साय ने कहा कि आदिवासी समुदाय के 'धरती आबा' के नाम से पूजनीय बिरसा मुंडा ने 19वीं सदी के

अंत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और स्थानीय शोषकों के खिलाफ एक अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात किया था, जिसे इतिहास में 'उलगुलान' के नाम से जाना जाता है।

उल्लेखनीय है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के पारंपरिक 'खुंटकट्टी' (सामुदायिक स्वामित्व) भूमि अधिकारों को छीनने और अत्यधिक लगान थोपने का विरोध प्रारंभ कर दिया था।

बिरसा एक महान समाज सुधारक भी थे। उनके प्रयासों से जनजातीय समाज में एकता, स्वाभिमान और आत्म-स मान की अद्भुत चेतना जागृत हुई। भारत सरकार ने उनके राष्ट्र एवं समाज को दिए योगदान को स मानित करते हुए उनके जन्मदिन 15 नवंबर को प्रतिवर्ष 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की है।

यह दिन स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के अमूल्य बलिदान को स्मरण करने का अवसर है।

मु यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार इसी संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।

कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप ने जनजातीय समुदाय के पूर्वजों के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और सामाजिक सुधारों से प्रेरणा लेने का आव्हान युवाओं एवं भावी पीढ़ी से किया। उन्होंने कहा कि इन महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और सतत संवर्धन को आगे बढ़ाना हम सबकी जि मेदारी है।

कार्यक्रम में जगदलपुर के विधायक किरण देव ने बस्तर अंचल के जनजातीय समुदाय के क्रांतिकारी जननायक शहीद गुंडाधुर, डेबरीधुर, गेंदसिंह आदि के संघर्षों एवं योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि इन महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई और बस्तर के जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए अद्भुत त्याग किया। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में जनजातीय समुदाय की एकजुटता और उत्थान के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहे।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

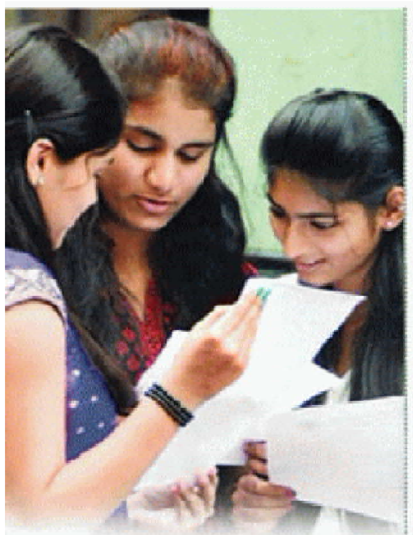

फ्रांस में नौकरी मिलना न तो नामुमकिन है और न ही आसान

पेरिस दुनिया की चार फैशन राजधानियों में से एक हैं ये वो जगह है जहां दुनिया के सबसे महंगे ब्रैंड जैसे ने जन्म लिया है। जब मैं भारत से यहां पढ़ाई के लिए पहुंचा तो मैं काफी नर्वस था। अब जब मैं पीछे देखता हूं तो अपने आप को काफी रिलैक्स महसूस करता हूं क्योंकि मेरा फैसला एकदम सही था।

दिल्ली के अनुविंद ने फ्रांस की एक फैशन कंपनी में नौकरी प्राप्त करके अपने सपनो को साकार किया है। उनके मुताबिक टाइम मैनेजमेंट न केवल आपको छोटे समय में फायदा पहुंचाता है बल्कि आपको इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए। फ्रांस में आकर मैंने जाना कि इंसान को उसी चीज से पहचाना जाता है जो उसने सीखी होती है। पेरिस दुनिया की चार फैशन राजधानियों में से एक हैं ये वो जगह है जहां दुनिया के सबसे महंगे ब्रैंड ने जन्म लिया है। जब मैं भारत से यहां पढ़ाई के लिए पहुंचा तो मैं काफी नर्वस था। अब जब मैं पीछे देखता हूं तो अपने आप को काफी रिलैक्स महसूस करता हूं क्योंकि मेरा फैसला एकदम सही था।

बिजनेस स्कूल को चुनना

मुझे मार्केटिंग का जुनून था क्योंकि इसमें लोगों से मिलना, इनोवेशन और क्रिएटिविटी शामिल थी। ग्रेजुएशन के दौरान मार्केटिंग मेरा फेवरेट था। संभावित ग्राहक की इच्छा और जरुरतों को समझना, सुपरमार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट और मार्केटिंग रणनीति चलाने के लिए डेटा को समझना आदि मुझे हर चीज में स्पेशलाइज करना था। इन सबके ऊपर पिछले कुछ सालों में मुझे फैशन और लग्जरी इंडस्ट्री से लगाव हो गया है। भारत, चीन, तुर्की, रूस और मैक्सिको में उभरती मार्केट्स के साथ यह वो इंडस्ट्री है जो मंदी के दौरान भी अच्छी गति से बढ़ रही थी। मुझे मार्केटिंग में ऐसी डिग्री प्राप्त करनी थी जिसका फोकस फैशन पर हो। गूगल पर सर्च करने के दौरान मुझे पता कि ऐसे केवल कुछ ही संस्थान हैं और इसमें से कुछ बेस्ट बिजनेस स्कूल फ्रांस में हैं। इसके बाद मैंने बिना देर किए जीमैट की तैयारी की और अपने ऐडमिशन के लिए मेहनत करने लगा। अचानक एक दिन सुबह मुझे संस्थान से ईमेल मिला कि मेरा चयन हो गया है।

जिंदगी बदलने वाला अनुभव

शुरुआती हफ्ते में मुझे काफी अजीब और उत्साहवर्धक लगा। अजीब इसलिए लगा क्योंकि यह मेरे लिए एकदम नई शुरुआत थी 30 से ज्यादा देशों के छात्र मेरी क्लास में थे। उत्साहवर्धक इसलिए लगा क्योंकि यहा सीखने के लिए काफी कुछ था।

करियर और उसके बाद

मैं हमेशा से ही फैशन और लग्जरी इंडस्ट्री में काम करना चाहता था और इस स्ट्रीम में मैंने श्वष्ठ।।श्वष्ट से स्पेशलाइजेशन किया था। फ्रांस में नौकरी मिलना ना तो नामुमकिन है और न ही आसान। मुझे काफी फायदा हुआ। फ्रांस के टॉप संस्थान से ग्रेजुएशन करना अपने आप में गर्व की बात थी। पढ़ाई के दौरान मुझे कई जगह इंटर्नशिप करने का मौका मिला। मैंने इंटर्नशिप की जो एक बड़ी फैशन और कॉस्मैटिक कंपनी है। फ्रांस ने केवल पेशेवर तरीके से मेरी मदद की बल्कि मुझे किराए पर कमरा दिलाने और पेपरवर्क में आसानी के लिए फ्रेंच भी सिखाई। मैं पेरिस में रहने से अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। यह दुनिया की फैशन कैपिटल है।

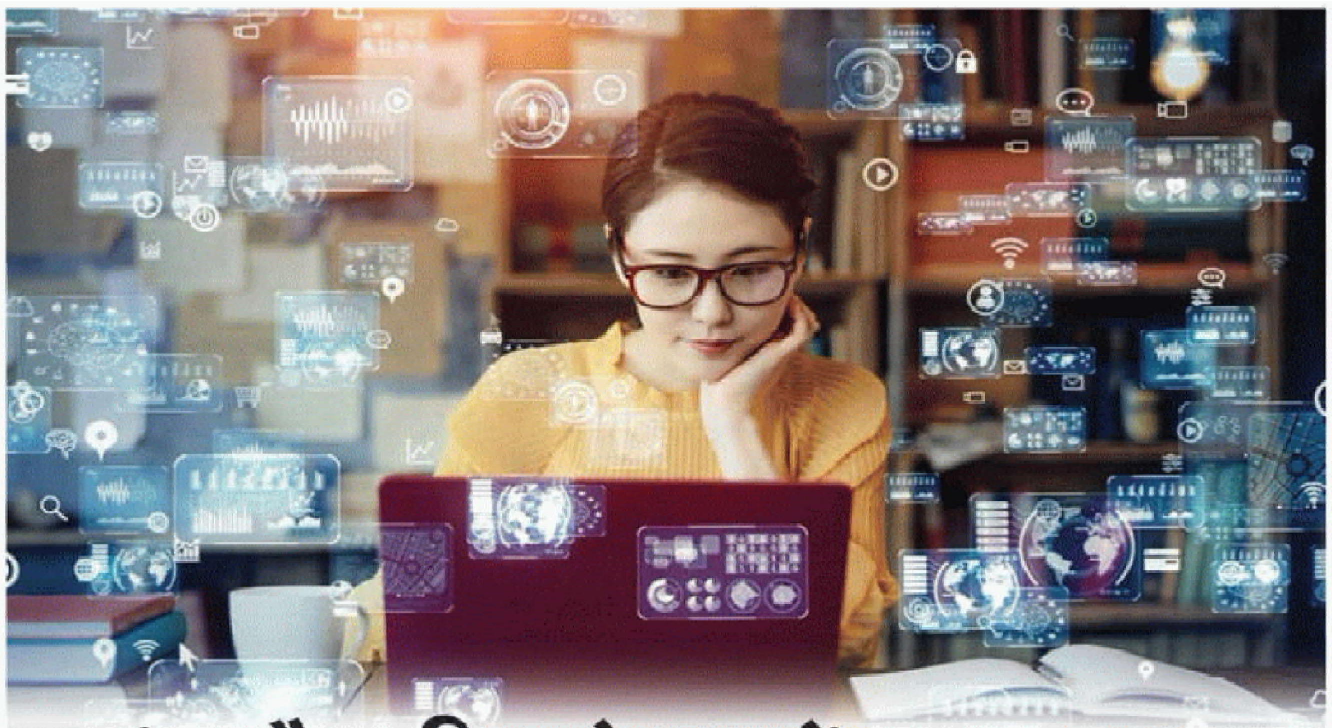

साइंस और गणित के छात्रों की तरह ह्यूमैनिटीज में भी हैं कई करियर विकल्प

ह्यूमैनिटीज के छात्रों के पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। अगर आप भी ह्यूमैनिटीज के छात्र हैं और अपने लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यह आर्टिकल आपकी मदद करेगा। इस आर्टिकल में हमने कई सारे टॉप करियर ऑप्शन के बारे में बताया है।

ह्यूमैनिटीज क्षेत्र के छात्रों के पास भी साइंस और गणित के छात्रों की तरह कई करियर विकल्प होते हैं, जिनमें उन्हें अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार चुनने का विकल्प होता है। ये छात्र शिक्षा, जर्नलिज्म आदि में अपना करियर बना सकते हैं। इन क्षेत्रों में काम करने के लिए उन्हें उनकी सामाजिक समझ, कम्युनिकेशन स्किल, और क्रिएटरनेस का उपयोग करना पड़ता है। आइए जानते हैं इन जॉब्स के बारे में।

जर्नलिज्म

जर्नलिज्म को देश का चौथा पिलर माना जाता है। डिजिटलीकरण के बाद से इसमें पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। अगर आपकी जर्नलिज्म में रूचि है तो आप इस क्षेत्र में जरुर जाएं। आप न्यूज़ रिपोर्टर, फीचर राइटर, एडिटर, मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट, संवाददाता या न्यूज एंकर बनकर अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं।

लॉ

लॉ बहुत ही प्रेस्टीजियस फ़ील्ड में से एक है। आप एलएलबी करने के बाद विभिन्न फर्म, कंपनियों और गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन में लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं। अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ आप लीगल एडवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं और क्लाइंट को विभिन्न समस्याओं पर सलाह दे सकते हैं। आप वकील के रूप में कोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी परीक्षा की तयारी करके जज बनना भी एक बहुत अच्छा विकल्प है ।

टीचिंग

टीचिंग की जॉब एक बहुत ही अच्छी जॉब होने के साथ-साथ बहुत सम्माननीय जॉब भी होती है। यह एक चुनौतीपूर्ण करियर भी है, जिसमें आपको एजुकेशन के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करना पड़ता है। भारत में योग्य शिक्षकों की मांग सभी स्तरों पर बहुत ज्यादा है। अगर आपकी रुचि भी शिक्षा और उससे संबधित क्षेत्र मे है तो आप एक टीचर बनकर बच्चे जो देश का भविष्य होते हैं उन्हें सही मार्ग दिखाकर देश की प्रगति में सहयोग कर सकते हैं।

ह्यूमन रिसोर्स

ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही अच्छा करियर विकल्प हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोगों के साथ काम करने में रुचि रखते हैं और संगठन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए योगदान देना चाहते हैं। इसमें आप लोगों के मैनेजमेंट, विकास, और कार्यसंगठन से संबंधित काम करते हैं।

मास कम्युनिकेशन

मास कम्युनिकेशन विभिन्न माध्यमों के माध्यम से संचार की प्रक्रिया को समझने और समाचार, सूचना, और विचारों को साझा करने में मदद करता है। आप रेडियो जॉकी, विज्ञापन और ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, फिल्म और टेलीविजन निर्माता या डायरेक्टर बनकर इस फील्ड में काम कर सकते हैं।

एडवरटाइजिंग

अपने किसी भी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाना हो या पुराने के बारे में भी कोई जानकारी देनी हो तो एडवरटाइजिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसीलिए इस फील्ड में बहुत स्कोप है। इसमें आपके प्रभावी ढंग से लिखने और बोलने की क्षमता जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। आप एडवरटाइजिंग मैनेजर बनकर अभियानों के लिए योजनाओं का फ्रेमवर्क तैयार करने का काम करते हैं।

राइटिंग और एडिटिंग

राइटिंग कोई नया फील्ड नहीं है जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है लेकिन यह फील्ड इतना बड़ा है कि इसमें ना तो कभी जॉब्स की कमी होती है और ना ही कभी इंसान बोर हो सकता है अगर आपको लिखने में रूचि है तो आप कॉपीराइटर और कंटेंट व्राइटर बनकर कंपनियों, विज्ञापन एजेंसियों, वेबसाइटों, ब्लॉगों, या ई-कॉमर्स साइटों के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। आप प्रेस एजेंट और पब्लिक रिलेशन्स व्राइटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल लेखक बनकर किताब, आर्टिकल और मैगजीन लिखने का काम कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन - ह्यूमैनिटीज के छात्रों के पास अक्सर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती हैं। जिससे उनके लिए पब्लिक रिलेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या मार्केटिंग में करियर बनाना आसान हो जाता है। आप विज्ञापन एजेंसियों, पब्लिक रिलेशन फर्मों या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभागों जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं।

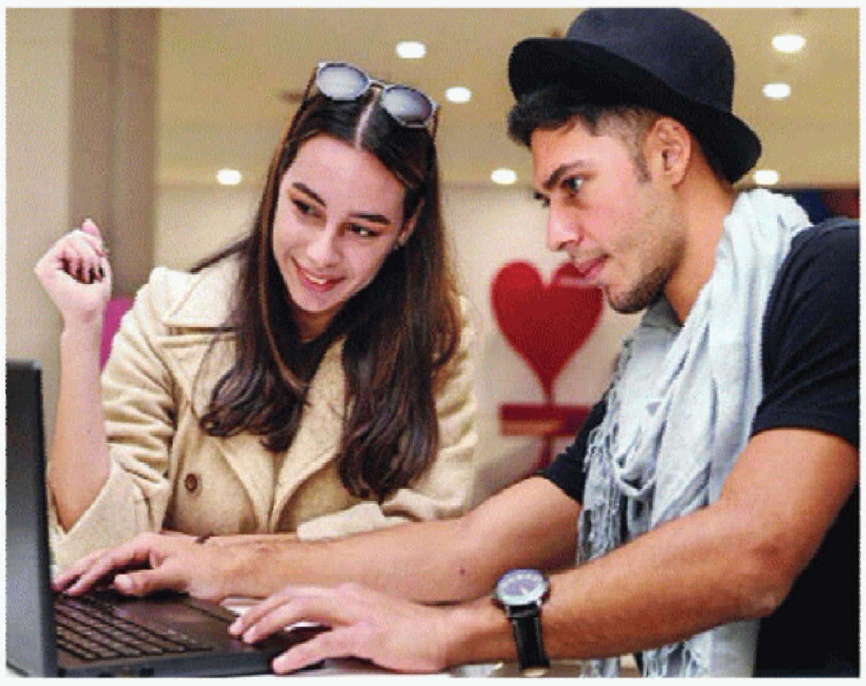

एमसीए करने के 5 बड़े फायदे

मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस (एमसीए) दो साल का स्नातकोत्तर कार्यक्रम है। यह डिग्री आपको कंप्यूटर एप्लिकेशन डेवलपमेंट और कई तरह की प्रोग्रामिंग भाषाओं की गहन समझ हासिल करने में मदद करती है। साथ ही साथ सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल स्किल भी प्रदान करती है। ऐसे में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस (एमसीए) करना एक शानदार फैसला साबित हो सकता है।

एडवांस्ड नॉलेज

एमसीए कार्यक्रम में स्पेशल कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम शामिल हैं। आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म से लेकर नेटवर्क सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक नवीनतम तकनीकों में गहन ज्ञान और व्यावहारिक विशेषज्ञता हासिल करेंगे। यह विशेष ज्ञान न सिर्फ आपकी तकनीकी क्षमताओं को निखारता है बल्कि आपको कठिन रोजगार बाजार में एक मूल्यवान उम्मीदवार बनाता है।

करियर ग्रोथ

आज के डिजिटल युग में कंपनियों में योग्य आईटी कर्मचारियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में एमसीए की डिग्री आपको आकर्षक नौकरी के अवसरों का लाभ उठाने और तेजी से कैरियर में ग्रोथ करने में सक्षम बनाती है। चाहे आपका सपना प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर विश्लेषक या फिर प्रोग्राम आर्किटेक्ट या आईटी सलाहकार ही बनना हो। इन सबके अलावा एमसीए आपको करियर के कई अन्य मौके भी देता है।

विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डिग्री

एमसीए की डिग्री को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जो छात्रों को देश और विदेश दोनों जगहों पर नौकरी के अवसर तलाशने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। चाहे आपके कैरियर के लक्ष्य सरकारी संगठनों, तकनीक-आधारित स्टार्टअप्स ही क्यों न हों।

इंडस्ट्री के अनुसार

एमसीए को इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए छात्रों को आधुनिक तकनीकों जैसे सूचना सुरक्षा, ऑनलाइन कंप्यूटिंग, मशीन के एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बारे में जानने का मौका मिलता है। आज के प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजार में एमसीए की डिग्री रखने से काफी फायदा होता है क्योंकि कंपनियां आधुनिक कौशल और दक्षता को बहुत महत्व देती हैं।

नेटवर्किंग के अवसर

एमसीए करने से आपको शिक्षकों, अन्य छात्रों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ संबंध बनाने के कई मौके मिलते हैं। बिजनेस वर्कशॉप, इंटर्नशिप, गेस्ट लेक्चर्स, पूर्व छात्र सम्मेलन या अन्य माध्यमों से छात्रों को ऐसे लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है जो उन्हें महत्वपूर्ण सलाह, करियर संबंधी सुझाव और मार्गदर्शन दे सकते हैं। एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क विकसित करना न केवल आपको अच्छी नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाता है बल्कि कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में दिलचस्प करियर के द्वार भी खोलता है।

साउंड इंजीनियरिंग के टॉप करियर ऑप्शन

साउंड इंजीनियरिंग एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आर्ट और साइंस एक साथ आते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न मीडिया जैसे कि वीडियो गेम, संगीत, फिल्में, टेलीविजन और रेडियो में उपयोग करने के लिए ऑडियो को बनाना, मिक्स करना, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग का मुश्किल प्रोसेस शामिल है।

किसी विशेष कार्य के लिए बेस्ट ऑडियो गुणवत्ता की गारंटी देना ही साउंड इंजीनियरिंग है। इसके डायवर्स क्षेत्र को तकनीकी विशेषज्ञता और आर्टिस्टिक सेंसटिविटी दोनों में स्ट्रोंग बेस की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के पेशेवरों को साउंड फिजिक्स में काबिल होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के ऑडियो उपकरणों में निपुण होना चाहिए और ऑडियो क्रिएशन की आर्ट में कुशल होना चाहिए। एक साउंड मिक्सिंग इंजीनियर वह व्यक्ति होता है जो ऑडियो की आर्ट और साइंस को जानता है। यह व्यक्ति ऑडियो एलेमेंट्स को मिक्स और बैलेंस करता है। इस आर्टिकल में साउंड इंजीनियरिंग की दुनिया, योग्यताओं, करियर विकल्पों के बारे में बताया गया है।

म्यूजिक प्रोडक्शन

संगीत रिकॉर्ड करने और बनाने के लिए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में साउंड इंजीनियर संगीतकारों के साथ काम करते हैं। वे सावधानीपूर्वक अलग-अलग लेवेल्स को मिक्स करते हैं और ट्रैक बनाते हैं, जिससे संगीत रचनाओं की साउंड टेपेस्ट्री बनती है।

लाइव साउंड

इस डोमेन के विशेषज्ञ एथलेटिक इवेंट, थिएटर शो और संगीत कार्यक्रम जैसे लाइव इवेंट के दौरान ऑडियो को सँभालते हैं। इसका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि दर्शकों को एररलेस ऑडियो अनुभव मिले।

फिल्म और टेलीविजन

विजुअल मीडिया के दायरे में, साउंड इंजीनियर फिल्मों, टीवी सीरीज और विज्ञापनों के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करने और एडिट करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। उनकी विशेषज्ञता डायलॉग और साउंड इफैक्ट्स में जान डाल देती है।

गेमिंग इंडस्ट्री

साउंड इंजीनियर डीप और कंपलेक्स साउंड लैंडस्केप को और प्रभावी बनाकर गेमिंग डोमेन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे आपको रियल गेमिंग अनुभव मिलता है।

रेडियो और प्रसारण

रेडियो स्टेशन और प्रसारण स्टूडियो, ऑडियो की हाईएस्ट क्वालिटी बनाए रखने के लिए साउंड इंजीनियरों पर बड़े पैमाने पर निर्भर करते हैं। ये प्रोफेशनल सुनिश्चित करते हैं कि रेडियो प्रसारण और अन्य ऑडियो सामग्री लगातार कड़े मानकों को पूरा करें।

पोस्ट-प्रोडक्शन

पोस्ट-प्रोडक्शन में विशेषज्ञता रखने वाले साउंड इंजीनियर इनिशियल रिकॉर्डिंग फेज के बाद परियोजनाओं पर काम शुरू करते हैं, विशिष्ट परियोजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक ऑडियो रीसर्च और एडिटिंग करते हैं।

कलिंग समाचार

संपादकीय

मंगलवार 18 नवंबर 2025

वक्फ़ बोर्ड-मुस्लिमों की सुने सरकार!

भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार द्वारा वक्फ़ संशोधन कानून के जरिये जैसे बदलाव प्रस्तावित हैंए उनके खिलाफ़ देश भर के मुस्लिमों में नाराज़गी है। इसकी बानगी सोमवार को दिल्ली के जंतर.मंतर पर दिखी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि वक्फ़ कानून संशोधन विधेयक ;2024द्ध वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन होगा। बोर्ड के अतिरिक्त जमाते इस्लामी व जमीयत उलेमा.ए.हिन्द जैसे कई और संगठन शामिल हुए जो कि देश के अल्पसं यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले से ही सरकार इस बात से वाकिफ़ है कि मुस्लिम संगठनों की इससे नाराज़गी है। बेहतर होगा कि सरकार इस कानून को लाने का विचार ही त्याग दे। वैसे भी जब संशोधन कानून लाया गया तभी संसद के अलावा देश भर के मुस्लिमों तथा उन तमाम नाराज़ हैं जो नागरिकों की धार्मिक आज़ादी के पक्षधर हैं। हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर केन्द्रीय अल्पसं यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी सरकार के चिर.परिचित अंदाज में कांग्रेस तथा विपक्ष पर दोष मढ़ दिया और कहा कि वह इस कानून को लेकर देश भर में झूठ फैला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून मुस्लिमों के हित में है। एक तरह से देश भर के वक्फ़ों से उनकी ज़मीनें छीन लेने की साफ मंशा सरकार की दिखाई देती है। अब तक मस्जिदों को संचालित करने एवं उनका प्रबंधन करने वाले बोर्ड के काम.काज में संशोधित कानून के जरिये सरकार की न केवल दखलंदाजी बढ़ेगी बल्कि सभी स्थानों पर देश के प्रमुख दो स प्रदायों. हिन्दुओं व मुस्लिमों के बीच दूरी भी बढ़ेगी। बोर्ड पर सरकार या स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण होने से मस्जिदों का रखरखाव भी कठिन हो जायेगा। याद हो कि 2024 में सरकार संसद में वक्फ़ संशोधन अधिनियम लेकर आई थी जिसका दोनों सदनों में तीव्र विरोध हुआ था। विपक्ष की मांग के आगे झुकते हुए इसे संयुक्त संसदीय समिति ;जेपीसीद्ध के पास भेजा गया था लेकिन उसमें सत्तारुढ़ भाजपा का बहुमत होने के कारण इसमें वे सारे संशोधन शामिल करने की सिफारिशें की गयीं जो कि सरकार या यूं कहें कि भाजपा चाहती है। लोगों में एक आम धारणा यह फैलाई गई है कि वक्फ़ के पास अकूत ज़मीनें हैं जिनके बल पर मुस्लिमों की राजनीति होती है। सच तो यह है कि वक्फ़ की जमीनों एवं अन्य परिस पत्तियों से ही मस्जिदों का खर्च निकलता है। आम धारणा यह भी हैए जो कि सुनियोजित तरीके से फैलायी गयी है कि मस्जिदों में देश विरोधी तथा हिन्दू विरोधी कार्यक्रम चलाये जाते हैं। दरअसल यह भी भाजपा द्वारा ध्रुवीकरण का एक टूल है जो उसे हिन्दुओं के वोट दिलाने में मददगार साबित होता है। नये कानून के जरिये एक तरह से पूरा नियंत्रण सरकार के हाथों में चले जाने से मुस्लिमों को उनके धार्मिक कार्यक्रमों को स पन्न करने में न केवल कठिनाई आयेगी वरन दैनंदिन के कामों के लिये भी जिला प्रशासन पर निर्भर होना पड़ेगा। यह एक तरह से एक समुदाय की धार्मिक आज़ादी में हस्तक्षेप होगा। इन कारणों से यदि मुस्लिम समुदाय प्रस्तावित कानून से नाराज़ है तो वह स्वाभाविक ही है। जंतर.मंतर पर प्रदर्शन उसी नाराज़गी के कारण होने वाला प्रदर्शन कहा जा सकता है जिसमें शामिल होने के लिये आयोजकों ने न केवल जेपीसी के सदस्यों को आमंत्रित किया बल्कि भाजपा के नेतृत्व में बने नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस के सदस्यों से भी ऐसा ही आग्रह किया है। इस कानून के विरोध पर रिजिजू का कहना वैसा ही है जैसा कृषि कानून पर सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित विभिन्न मंत्री कहते आये थेए कि यह कानून किसानों के हित में है। यह समझ से परे है कि भाजपा सरकार जो भी कानून लाती है वह किसी न किसी के हित में होने का दावा करती हैए लेकिन सिर्फ उन्हें पता नहीं होता जिसका हित सरकार करना चाहती है। नोटबन्दी जनता के हित में थी पर जनता की समझ में नहीं आईए जीएसटी व्यवसायियों के हित में थी पर व्यवसायियों की समझ में नहीं आई और उन्होंने विरोध किया, कृषि कानून किसानों के हित में था पर किसानों की समझ में नहीं आया और उन्होंने विरोध कियाए संविधान की अनुच्छेद 370 का विलोपन ज मू.कश्मीर के हित में था परन्तु वह वहां के नागरिकों की समझ में नहीं आया और उन्होंने विरोध किया.

एकता का स्वांग, बंटवारे की भाषा!

राजेंद्र शर्मा

कथित राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 शुरू से आखिर तकए ऐसी मनमानी का ही उदाहरण है। संघ.भाजपा के विशेष एजेंडे और हिंदुत्व.कारपोरेट गठजोड़ को आगे बढ़ाने के स्पष्ट्ढ उद्देश्य के साथए इस शिक्षा नीति को सूत्रबद्ध करने की कई साल लंबी कसरत सेए राज्यों को बाहर ही रखा गया थाए जो अन्य चीजों के अलावा इस कसरत का इस देश की समृद्ध विविधता से विमुख बने रहना ही सुनिश्चित करता था।

भाषा के प्रश्न पर और खासतौर पर क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे परए दक्षिण भारत एक बार फिर गर्म हो रहा है। इसका उबाल तमिलनाडु में खासतौर पर ज्यादा हैए जहां पहले भी 1960.70 के दशकों मेंए भाषायी प्रश्न पर उग्र विरोध सामने आया था। बहरहालए कम से कम इस बार भाषा विवाद का जोर पकड़ना इस अर्थ में अनावश्यक था कि यह विवाद केवल केंद्र सरकार के इकतरफा कदमों और इकतरफा फैसलों पर प्रतिक्रिया के रूप में भड़का है। यह कोई संयोग ही नहीं है कि साठ.सत्तर के दशकों को पीछे छोड़कर देश अगर बाद के दशकों में भाषायी अशांति से बहुत दूर निकल आया थाए तो इसमें भाषायी विवाद में सामने आयी संवेदनाओं के प्रतिए बाद में आयी केंद्र सरकारों के संवेदनशीलता प्रदर्शित करने का भी हाथ था। लेकिनए मोदी राज में इस तरह की संवेदनशीलता की जगहए मराठी की संज्ञा का उपयोग करें तो केंद्र और सत्ताधारी ताकतों की ठोकशाही ने ले ली है। इसका नतीजा साठ.सत्तर के भाषायी विवाद के साए फिर से सिर पर मंडरा रहे होने के रूप में सामने है।

जैसाकि सभी जानते हैंए विवाद के वर्तमान चक्र की शुरूआत केंद्र सरकार द्वारा इकतरफा तरीके से तमिलनाडु के शिक्षा से संबंधित फंड रोके जाने के साथ हुई थी। इस सिलसिले को चलते करीब दो साल हो जाने और राज्य का इस तरह रोका गया फंड दो हजार रुपए से ऊपर निकल जाने के बादए अब तक शिष्टता से इस मुद्दे को उठाती रही तमिलनाडु सरकार कोए विरोध का अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। लेकिनए मोदी सरकार को इस तरह के किसी विरोध की सुनवाई करना तो दूर रहाए विरोध की ऐसी आवाज को बर्दाश्त करना भी मंजूर नहीं होता है। राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा हैए कहने की रस्म.अदायगी के फौरन बादए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फंड रोके जाने के लिए तमिलनाडु को ही यह कहकर दोषी ठहराना शुरू कर दिया कि समस्या उसके ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 को लागू न करने में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होए फंड खुद ब खुद आ जाएंगे! कहने की जरूरत नहीं है कि यह केंद्र के हाथों से निकलने वालेए केंद्रीय कार्यक्रमों के फंड कोए राज्यों पर नीतिगत मामलों में बड़ी नंगई से केंद्र सरकार की मनमर्जी थोपे जाने का औजार बनाए जाने का ही मामला है। यह देश की संघीय व्यवस्था के खिलाफ हैए जिसकी इजाजत देश का संविधान नहीं देता है। कोई भी स्वाभिमानी राज्यए केंद्र के इस तरह मनमर्जी थोपने का विरोध करेगा। और शिक्षा जैसे मामलों मेंए जो संविधान की समवर्ती सूची में आने के बावजूदए मु यतरू राज्य के अधिकार का विषय बना हुआ हैए केंद्र की ऐसी मनमानी तो हर्गिज स्वीकार नहीं की जा सकती है। लेकिनए मोदी राज में तो केंद्र के इस तरह की मनमर्जी चलाने को ही सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है।

कथित राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 शुरू से आखिर तकए ऐसी मनमानी का ही उदाहरण है। संघ.भाजपा के विशेष एजेंडे और हिंदुत्व.कारपोरेट गठजोड़ को आगे बढ़ाने के स्पष्ट्ढ उद्देश्य के साथए इस शिक्षा नीति को सूत्रबद्ध करने की कई साल लंबी कसरत सेए राज्यों को बाहर ही रखा गया थाए जो अन्य चीजों के अलावा इस कसरत का इस देश की समृद्ध विविधता से विमुख बने रहना ही सुनिश्चित करता था। दूसरी ओरए संबंधित कमेटी में शुरू से ही कारपोरेट नजरिए का बोलबाला सुनिश्चित किया गया था। इस तरह सरासर गैर.प्रतिनिधि तरीके सेए संघ.कारपोरेट गठजोड़ के आग्रहों को आगे ले जाने का पूरा बंदोबस्त करने और छात्रोंए शिक्षकोंए अभिभावकों आदिए शिक्षा में सबसे ज्यादा हित.रखने वाले सभी तबकों की आवाजों को बाहर रखने के बादए एक दक्षिणपंथी विचारधारात्मक आग्रहों से लदा मसौदा तैयार करने के बादए रस्मअदायगी के तौर पर लोगों की राय लेने के लिए रखा जरूर गयाए लेकिन जैसाकि पहले से अनुमान लगाया जा सकता थाए विभिन्न हितधारकों की रायों को और तमाम आलोचनात्मक रायों कोए सिरे से अनसुना कर दिया गया।

इसके ऊपर सेए 1968 तथा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के विपरीतए इस शिक्षा नीति को सीधे केंद्र द्वारा इकतरफा तरीके से देश पर थोप दिया गया। इस नीति पर न सिर्फ राज्यों की कोई राय नहीं ली गयीए राज्यों को साथ लेकर चलना तो उसकी दृष्टि में भी नहीं था। उल्टे केंद्र ने पूरे देश की ओर से नीति बनाने का अधिकार खुद ब खुद अपने को दे दिया था। इसके ऊपर सेए संसद को भी इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं दी गयी और इस तरह वृहत्तर राजनीतिक राय को इस समूची प्रक्रिया से दूर ही रखा गया। केंद्र सरकार ने ही कमेटी का गठन किया और उसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनी मंजूरी सेए देश पर थोप भी दिया। हैरानी की बात नहीं है कि गैर.भाजपायी राज्यों में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनेक पहलुओं को विभिन्न स्तरों पर उपेक्षाए असहयोग से लेकर प्रतिरोध तक का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में यह विरोध सबसे बढ़करए त्रिभाषा फार्मूले के लागू किए जाने के नाम परए हिंदी के थोपे जाने के विरोध के रूप में सामने आया है। बेशकए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा परए खासतौर पर प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जोर दिए जाने की बात कही गयी है। लेकिनए इसके साथ ही इसमें छोटे बच्चों के बीच बहुभाषिकता को पोसने पर भी काफी जोर दिया गया हैए जिसकी शिक्षा.विज्ञानी वैज्ञानिकता पर सवाल उठ सकते हैं। बहरहालए इसमें भी विशेष रूप से समस्यापूर्ण हैए त्रिभाषा फार्मूले के नाम पर तमिलनाडु में तमिल और अंग्रेजी के अलावाए हिंदी थोपने का आग्रह। वैसे तो मोदी सरकार जब से सत्ता में आयी हैए केंद्र द्वारा हिंदी थोपे जाने की शिकायतें उठती ही रही हैं। बहरहालए त्रिभाषा फार्मूले के लागू किए जाने के केंद्र के फरमान और इस फरमान को थोपने के लिए शिक्षा के लिए राज्य के फंड तक रोकने की उसकी दादागीरी नेए चीजों का विस्फोटक बिंदु तक पहुंचा दिया है।

बेशकए त्रिभाषा फार्मूला जिसका तमिलनाडु प्रतिरोध कर रहा हैए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही खोज नहीं है। तीन भाषाओं पर आधारित फार्मूला पहले से शिक्षा नीति का हिस्सा रहा था। लेकिनए एक तो उसे इस तरह अनिच्छुक राज्यों पर थोपने की कोशिश पहले नहीं की गयी थी। इसके ऊपर सेए 2020 की शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूले में भी तरह.तरह के बदलाव कर दिए गए हैंए जो इस फार्मूले के जरिए वास्तव में किसी बड़े पैमाने पर तथा सही मायने में बहुभाषिकता सुनिश्चित करने के बजायए इसे किसी न किसी प्रकार से गैर.हिंदीभाषी राज्यों पर हिंदी लादे का जाने ही फार्मूला बना देता है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह संस्कृत की पढ़ाई की ओट लेकरए त्रिभाषा फार्मूले में विश्वास के पाखंड के बावजूदए हिंदी भाषी क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा सीखने से दूर रखा जाता रहा है।

हैरानी की बात नहीं है कि पिछले ही दिनों आया एक अध्ययन यह दिखाता है कि हिंदीभाषी क्षेत्र 90 फीसदी एकल.भाषी है और सबसे कम बहुभाषिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस असंतुलन को और बढ़ाने ही जा रही है। नयी नीति में इसी छल को विदेशी भाषाओं की पढ़ाई का प्रावधान जोड़ने के जरिए और आगे बढ़ाया गया है। वास्तव में मातृभाषा में शिक्षा के पहलू से भी आरंभिक शिक्षा को आज बढ़ती चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे के आठवें चक्र सेए जो एनसीईआरटी द्वारा किया गया भाषायी माध्मम पर आखिरी अखिल भारतीय सर्वे हैए पता चलता है कि वास्तव में मातृभाषा में पढ़ाने वाले स्कूलों का अनुपात घटने के बजाय बढ़ ही रहा है। आठवें सर्वे के समय 86ण्62 फीसदी स्कूल मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दे रहे थेए जबकि सातवें सर्वे के समय यही अनुपात 92ण्07 फीसदी था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रए दोनों में यह हिस्सा घट रहा था। इससे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकताओं का ही पता चलता है कि यह नीति तमिलनाडु से त्रिभाषा फार्मूला लागू कराने के लिए झगड़ रही हैए न कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के अनुपात में गिरावट के खिलाफ कोई अभियान चला रही हैए क्योंकि यह गिरावट तो शिक्षा के उस बढ़ते निजीकरण तथा व्यापारीकरण का ही नतीजा हैए जिसे यह शिक्षा नीति बड़ी नंगई से प्रमोट करती है। हैरानी की बात नहीं है कि तमिलनाडु राज्य ने भी केंद्र की मनमानी की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। मु यमंत्री एम के स्टालिन ने कह दिया है कि केंद्र कितने ही फंड रोक लेए तमिल झुकेंगे नहीं। इस तरहए जिस हिंदी के पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा होने का दावा किया जाता हैए उसे केंद्र की रीति.नीति ने तोड़ने वाली भाषा बनाकर रख दिया है। देश को और ज्यादा एकजुट करने के दावे के साथए ऐसे ही तोड़ने का काम ज मू.कश्मीर से लेकर मणिपुर तक के मामले में किया गया है। एकता का झूठा मंत्रजाप करते.करतेए देश को बढ़ते विभाजन के रास्ते पर धकेला जा रहा है।

पुरानी टीम में आधे भाजपा के-क्या इन्हीं के साथ अहमदाबाद अधिवेशन होगा?

शकील अख्तर

गुजरात के बाहर के कांग्रेसी नेता चिंतित नहीं हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने यह केवल गुजरात के लिए कहा है। हरियाणा के लिए नहींए राजस्थान के लिए नहीं। जहां के कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा से मिलकर जीते हुए विधानसभा चुनाव हरवा दिए। कांग्रेस मु यालय में दूसरे लोगों के लिए नहीं।

क्या कांग्रेस ऐसे ही आधे संघियों को लेकर अहमदाबाद अपने पूर्ण अधिवेशन ;प्लेनरीद्ध में पहुंच जाएगीघ् अगले माह अप्रैल में होना है। 8 और 9 तारीख को उसी अहमदाबाद में जहां राहुल ने कहा कि पार्टी में पचास प्रतिशत लोग भाजपा के भरे पड़े हैं। इनके दिल में और खून में कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस में रहकर भाजपा का काम कर रहे हैं।

बहुत स्पष्ट भाषण था राहुल का। शनिवार 8 मार्च को अहमदाबाद में। कार्यकर्तओं से बात करते हुए। कार्यकर्ता बहुत खुश हुए। दिल से तालियां पीटीं। जो बात वे हमेशा से कह रहे थे वह राहुल ने कह दी। एकदम साफ शब्दों में। कोई इसे हल्का नहीं कर सकता। दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकता।

गुजरात के बाहर के कांग्रेसी नेता चिंतित नहीं हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने यह केवल गुजरात के लिए कहा है। हरियाणा के लिए नहींए राजस्थान के लिए नहीं। जहां के कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा से मिलकर जीते हुए विधानसभा चुनाव हरवा दिए। कांग्रेस मु यालय में दूसरे लोगों के लिए नहीं जो कांग्रेस में बैठकर राहुल को गालियां देते हैं और मोदी की तारीफ करते हैं।

गुजरात के बाहर के लोगों की बात सुनकर ऐसा लगता है कि उन्हें भाजपा के साथ मिले रहने की छूट है। राहुल एक काम करें कि कांग्रेस मु यालय में एक पोलिंग बूथ बनवा लें। तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि जो आधे बीजेपी वाले कह रहे थे उससे बहुत ज्यादा हैं।

कांग्रेस में संघ की यह घुसपैठ आज की नहीं है बहुत पहले से है। और उस समय स्वाभाविक थी। आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पार्टी थी। सब विचारों के लोग आते थे। ज्यादातर अंग्रेजों से लड़ने के लिए मगर कई कांग्रेस में घुसकर नेहरू.गांधी को कमजोर करने के लिए। अंग्रेजों को फायदा पहुंचाने के लिए। मगर नेहरू नियंत्रण रखते थे। सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई। और कहा कि अगर आपके अंदर राष्ट्रप्रेम है तो कांग्रेस के साथ मिलकर काम कीजिए। बाद में इन्दिरा गांधी ने भी पहचाना और इन्हें अलग थलग करने के लिए अलग कांग्रेस ही बना दी। मगर उनके बाद पार्टी में विचार पूरी तरह खत्म हो गए। और दक्षिणपंथीए सा प्रादायिकए दलितए पिछड़ा विरोधी लोग छा गए। अब राहुल ने पहली बार इतने साफ शब्दों में पार्टी की असली सूरत सबके सामने रख दी। और अब अगर खुद राहुल भी यह कहें कि उन्होंने सिर्फ गुजरात के नेताओं के लिए कहा था तो कोई यकीन नहीं करेगा। पार्टी और कमजोर हो जाएगी। राहुल भी डर से अपनी बात से पलट रहे हैं यह खराब मैसेज पार्टी कार्यकर्ताओं तक चला जाएगा।

इसलिए अब राहुल के पास कोई रास्ता नहीं है। उन्हें पार्टी का पुनर्निर्माण करना ही होगा। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यह बात पहले ही कह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कबघ् खरगे को अध्यक्ष बने ढाई साल हो गए। मतलब नए नियमों के मुताबिक आधा कार्यकाल। अगर संशोधन नहीं होता पुरानी समयावधि रहती तो बिना संगठन में कुछ किए उनका कार्यकाल खत्म होने वाला होता। 2010 के संविधान संशोधन से पहले अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का ही होता था तो खरगे के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके साथ हैं। फिर देर क्यों? यही एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्रियंका गांधी लंबे समय से बिना किसी जि मेदारी के महासचिव हैं। अगर कांग्रेस प्रियंका को करिश्माई नेता मानती है तो उन्हें कोई महत्वपूर्ण जि मेदारी देने में देर क्यों कर रही हैघ् कोई जवाब नहीं!

अब सबसे बडा सवाल। क्या पार्टी के पूर्ण अधिवेशन ;प्लेनरीद्ध से बड़ा कोई जलसा होता हैघ् हर तीन साल में यह होता है। एआईसीसी के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जिनकी सं या अब तो हजारों में हो गई मगर कभी चार सौ.पांच सौ के आसपास होती थी। बड़ी स मानजनक चीज मानी जाती थी। लोग अपने नाम के साथ लगाते थे. एआईसीसी मेंबर।

तो इस पूर्ण अधिवेशन की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। अब तो कांग्रेस के मु यालय में लायब्रेरी खतम हो गई। पहले हर पूर्ण अधिवेशन की कार्रवाई का रिकार्ड छपा हुआ वहीं होता था। कौन.कौन से प्रस्ताव पास किए गए। पार्टी के आगे के दिशा क्या हैघ् कौन.कौन शामिल हुएघ् विदेशी प्रतिनिधि भी आते थे। कांग्रेस अध्यक्ष का भाषण। जिस पर अन्तरराष्ट्रीय निगाहें भी होती थीं। विदेश नीति पर प्रस्ताव पारित होता था। आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव। और हर अधिवेशन की 150.200 पेज की पूर्ण कार्रवाई प्रकाशित होती थी। यह 86वां अधिवेशन है। अगर अब पत्रकार शोध छात्र राजनीतिक लेखक पुराने अधिवेशनों के बारे में पढ़ना चाहें तो मुश्किल हो जाएगा। अकबर रोड स्थित मु यालय में लायब्रेरी खतम कर दी। बहुत साल पहले ही। 15 साल हो गए होंगे। बहुत किताबें रिफरेन्स के लिए थीं। लोग दूर.दूर से नोट्स लेने पढ़ने जानने आते थे। अब कहते हैं कि कोटला रोड पर बनाए नए आफिस में लायब्रेरी बनाएंगे। एकए कि लायब्रेरी एक दिन में नहीं बनती है। किसी भी संस्थान की प्रतिष्ठा इससे मालूम पड़ती है कि उसकी लायब्रेरी कितनी पुरानी है। वह अद्यतन अपडेट होती रहती है। दूसरी बातए वहां पत्रकार और दूसरे विजिटर्स की वैसी पहुंच नहीं है। जैसी अकबर रोड के मु यालय में है। तो लायब्रेरी वहां कितनी उपयोगी होगी कहना मुश्किल है।

खैर तो तैयारियों के सिलसिले की बात हो रही थी। तो सवाल यह है कि कर कौन रहा हैघ् वही पुराने पदाधिकारी! तो अगर उनको इतने महत्वपूर्ण काम में लगा रखा है तो फिर वहीं रहेंगे। अगर ऐसा है तो फिर अनाउंस कर देना चाहिए। और अगर नए लगाना है तो फौरन लिस्ट निकालना चाहिए। अब बचा तो एक महीने से कम है। मगर फिर भी तैयारी में शामिल हो सकते हैं।

कांग्रेस में कहा गया है यह 2025 संगठन का साल है। ठीक! मगर कबघ् जाते हुए 2025 में! तब तो बिहार चुनाव आ जाएंगे। एक ठोस बहाना। राहुल के कहने के बाद तत्काल करना चाहिए। आज राहुल कांग्रेस में पूरी तरह ताकत में हैं। कोई चुनौती नहीं। अध्यक्ष खरगे के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा है। दोनों मिलकर कुछ भी करेंगे कोई सवाल उठाने वाला नहीं। क्योंकि कार्यकर्ता और जनता भी राहुल और खरगे के साथ हैं। कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो विद्रोह कर सके। जैसा इन्दिरा जी केए राजीव गांधी के खिलाफ किया था। फिर भी अगर राहुल और खरगे कुछ नहीं कर पाते हैं तो दोष किसकाघ् दोनों नेताओं ने पार्टी की हर समस्या कमजोरी के बारे में खुलकर बात की है। तो फिर इन्हें दूर कौन करेगाघ् और कबघ

अभी संगठन में मामूली बदलाव हुआ है। 2 महासचिव और 9 इन्चार्ज नए बनाए। कुछ को विश्राम दिया गया। मगर 20 .22 से ज्यादा महासचिव और राज्यों के इन्चार्ज पुराने हैं। अभी अध्यक्ष ने एक मीटिंग बुलाई। 11 नए और 19 पुराने। जिनमें कुछ पुराने आए नहीं थे। बाकी राज्यों के अध्यक्ष जो सब प्लेनरी में जाएंगे पुराने होंगे। उनके राज्यों के एआईसीसी मेंबर भी पुराने होंगे। डिपार्टमेंटों के हेड भी पुराने होंगे।

क्या मतलब हैघ् इन्हीं को रखना है। रखिए। एक कांग्रेस के महासिचव थे। कहते थे हमारी कांग्रेस है। हम जो चाहे करें। आपको क्याघ् पूरा भट्टा बिठा कर गए। उसके बाद पार्टी उठ ही नहीं पाई। अभी शुक्र है कोई इस भाषा में नहीं बोल रहा। मगर हां गुटबाजी करने वालेए भाजपा की मदद करने वाले महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। राहुल और खरगे को सब मालूम है। लेकिन करते क्यों नहीं है और करते नहीं हैं तो बोलते क्यों हैंघ् यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है!

विविध समाचार

2022 में भी यही जवाब मिला, हेमंत के विधायक ने अपनी ही सरकार से पूछ दिया ऐसा सवाल, जिसको लेकर मच गया बवाल

रांची १७/११ (संवाददाता):मु यमंत्री हेमतं सोरेन ने विधानसभा की पहली पाली में ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर जवाब के क्रम में विपक्ष को उसकी जि मेदारी से अवगत कराते हुए सुझाव दिया कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में आइएनडीआए गठबंधन की सरकार है। इनके ऊपर ;भाजपाद्ध भी बहुत जवाबदेही है कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर बने। भारत सरकार राज्य में इंजीनियरिंग संस्थानों को मान्यता प्रदान करे। उन्होंने मंत्री सुदिव्य कुमार को निर्देशित किया कि अबतक इस संबंध में भारत सरकार से किए गए पत्राचार से विपक्ष को भी उपलब्ध कराएं। वे भी अपनी तरफ से पहल करेंगे। दरअसल झामुमो विधायक जिग्गा सुसारण होरो ने पोलिटेक्निक संस्थानों की मान्यता में हो रही देरी से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार से जवाब मांगा था। उन्होंने कहा कि जो जवाब उन्हें दिया गया हैए वही जवाब वर्ष 2022 में दिया गया था। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि लगातार इस संबंध में एआइसीटीसी से आग्रह किया जा रहा है। मु यमंत्री के निर्देश पर मंत्री

सुदिव्य कुमार ने कहा कि हम पठन.पाठन करना चाहते हैं। वे अबतक एआइसीटीसी से किए गए पत्राचार एवं छाया संचिका नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को प्रेषित कर देंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि विधायक अपने क्षेत्र के सांसद के साथ भी एआइसीटीसी के द तर जाएं। उधर बाबूलाल मरांडी ने मु यमंत्री हेमंत सोरेन के सुझाव पर कहा कि एआइसीटीसी स्वतंत्र संस्था है। 2022 से ऐसा चल रहा है तो उन्हें नहीं लगता कि गंभीरता से प्रयास हुआ है। राज्य में सभी जगह पोलिटेक्निक संस्थान प्रभार में चल रहे हैं। राज्य सरकार को इसे टालने की बजाय गंभीरता से काम करना चाहिए। मु यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरहुल मनेगा और बढ़िया से मनेगा। दरअसल रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सदन को सूचित किया कि रांची के सिरमटोली में लाइओवर के रैंप को लेकर सरना संगठनों ने सबका पुतला फूंका है। सरहुल आने वाला है। सीएम इसका पटाक्षेप करें ताकि सभी खुशी से सरहुल मना सकें। मु यमंत्री ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरहुल मनेगा और बढ़िया से मनेगा। डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने भाषा की वर्तनी का सवाल उठाते हुए आग्रह किया कि कुरमाली भाषा को कुड़माली कहा जाए। वर्तनी में सुधार किया जाना चाहिए। मु यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके सुझाव पर हामी भरते हुए कहा कि भाषा और बोलचाल में जो सही हैए उसपर कोई आपत्ति नहीं है। बात संज्ञान में आई है। आकलन कराकर सुधार होना चाहिए। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से बड़कागांव के भाजपा विधायक रोशनलाल चौधरी ने पीटीपीएस के विस्थापितों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के साथ वार्ता की पहल की जाए। हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार हरियाणा की तर्ज पर राज्य की जमीन अधिग्रहण नीति बनाए। अभी जमीन का न्यूनतम रेट लग रहा है। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सरकार विस्थापन आयोग बनाएगी। इसका नीतिगत निर्णय पूर्व में ही हो चुका है।

रांची की आदिवासी युवती से बरवाअड्डा में दरिंदगी करने वाला दोषी करार

धनबाद १७/११ (संवाददाता): रांची के मांडर की आदिवासी लड़की को नौकरी के नाम पर बहला.फुसलाकर बरवाअड्डा लाकर सामूहिक दुराचार के केस में कोर्ट ने मु य आरोपी परितोष पांडेय को दोषी करार दिया। वहीं इसी केस के तीन अन्य आरोपी प्रकाश हाजराए कुंदन हाजरा एवं गुड्डू कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया गया। यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह एससी एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को इस मुकदमे का जजमेंट की तिथि तय थी।कोर्ट ने सुनवाई के बाद परितोष को दोषी पाया। परितोष की सजा बिंदु पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। परितोष समेत प्रकाश हाजरा एवं गुड्डू कुमार न्यायिक हिरासत में धनबाद जेल में बंद हैंए वहीं कुंदन हाजरा जमानत पर जेल से बाहर था। आदिवासी युवती के साथ यह घटना 24 सितंबर 2018 की रात बरवाअड्डा के पंडुकी फुटबॉल मैदान में हुई थी। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। फिर ईंट.पत्थर से बुरी तरह मारकर उसे मरा समझकर आरोपी भाग निकले थे। अगले दिन सुबह उसे बेहद गंभीर अवस्था में एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया था। फिर रि स में इलाज हुआ।पंडुकी मैदान के पास झाड़ियों में अर्द्धनग्न हाल में युवती अचेत मिली थी। वह खून से लथपथ थी। प्रथमदृष्टया ही यह साफ हो गया था कि युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी जान लेने की कोशिश की गई। दुष्कर्म करने वाले उसे मरा समझ छोड़ गए। पुलिस ने आधार पंजीकरण रीडिंग डिवाइस से युवती की अंगुलियों का निशान लेकर उसकी पहचान की थी। दूसरे दिन युवती ने होश में आने पर अपना मोबाइल नंबर बताया। पीड़िता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल खंगाला शुरू किया तो पंडुकी निवासी परितोष पांडेय का मोबाइल नंबर मिला। घटना की रात और पहले भी युवती और परितोष के बीच मोबाइल पर बातचीत की पुष्टि हुई। मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने परितोष व अन्य को गिर तार किया।परितोष ने पूछताछ में पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि युवती से उसकी पहले से जान.पहचान थी। युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर बरवाअड्डा ले आया। पहले ही तीनों दोस्तों को बरवाअड्डा किसान चौक पर बुला रखा था। वहां से दोस्तों के साथ युवती को बाइक पर लेकर पंडुकी मैदान पहुंचा। फिर दोस्तों संग शराब पार्टी की। इसके बाद चारों ने मिलकर दरिंदगी की।पीड़िता के भाई ने भास्कर से बातचीत में बताया.गरीब होना अभिशाप है। पहले ही पिता एक दुर्घटना में एक पैर खो चुके हैं।

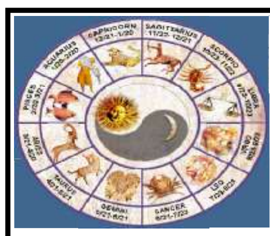

आज का राशिफल

मेष – आज के दिन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ विशेष रहेंगी। मन में द्विधा रहने से ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। पैसे की लेन–देन या आर्थिक व्यवहार न करने की गणेशजी की सलाह है।

वृषभ – गणेशजी कहते हैं कि व्यापार में वृद्धि होने के साथ व्यापार के स बंध में सौदे लाभदायक साबित होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। बुजुर्गों तथा मित्र मंडल से लाभ और सुखद क्षणों का अनुभव मिलेगा।

मिथुन – शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। नौकरी – व्यवसाय में आपके परिश्रम का मुआवजा मिलता हुआ प्रतीत होगा। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कर्क – गणेशजी कहते हैं कि आज आपकी भाग्य वृद्धि के साथ आकस्मिक धन लाभ होगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के प्रयास सफल होंगे। तथा विदेश से अच्छे समाचार आएँगे।

सिंह – आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। निषेधात्मक विचार आपको गलत मार्ग पर न ले जाए, उसका ध्यान रखने के लिए गणेशजी कहते हैं।

कन्या – गणेशजी की कृपा से दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। मनोरंजन की प्रवृत्तियों में भाग लेंगे। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी।

तुला – गणेशजी कहते हैं कि सामान्ज रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति के भी तबीयत में सुधार होगा। घर में सुख– शांति के वातावरण में आप समय व्यतीत करेंगे। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा।

वृश्चिक – आज यात्रा प्रवास का आयोजन न करने की सलाह गणेशजी देते हैं। स्वास्थ्य के स बंध में चिंतित रहेंगे। संतानों के स बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें।

धनु – गणेशजी कहते हैं कि आज आपको अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव खड़े होने की संभावना है। मन में उठनेवाली द्विधाओं से आप मानसिक उचाट अनुभव करेंगे।

मकर – आज आप रणनीति में शत्रुओं को परास्त करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। सफलता मिलेगी। आप हरेक कार्य तन–मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। व्यापार–धंधे में लाभ होगा।

कुंभ – गणेशजी बताते हैं कि मन में द्विधाएँ खड़ी होने से आप कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुँच सकेंगे। महत्त्वपूर्ण निर्णय न लें। वाणी पर संयम नहीं रहनेसे पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की संभावना है।

मीन – आनंद– उत्साह और तन–मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। नए कार्य हाथ में लेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। धार्मिक मांगलिक प्रसंगों में जाएँगे।

18 लाख महिलाओं को अब तक नहीं मिले मंईयां सम्मान योजना के पैसे, हेमंत सरकार को राफिया नाज ने दे दी चेतावनी

रांची १७/११ (संवाददाता): भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने राज्य सरकार द्वारा 18 लाख महिलाओं की मंईयां स मान योजना की राशि रोकने के आरोप को उनके स मान के नाम पर छल और विश्वासघात बताया है। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल एक झूठा वादा था कि सभी महिलाओं को मंईयां स मान की राशि मिलेगी। 18 लाख महिलाओं को अब तक एक भी रुपये नहीं मिले हैं।

राफिया ने कहा कि महिला स मान की बात करने वाली सरकार ने 18 लाख माताओंए बहनों और बेटियों के हक को कुचला है।मंईयां स मान के तहत सरकार द्वारा जारी किए गए ना तो हेल्पलाइन नंबर काम कर रहे हैंए ना ही वेबसाइट पर कोई सुनवाई हो

रही है।सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सभी महिलाओं को जल्द मंईयां स मान की राशि नहीं मिलीए तो भाजपा आंदोलन करेगी।प्रतापपुर ;चतराद्ध में झारखंड सरकार की महत्वकांक्षी योजना मंईयां स मान की राशि नहीं आने से महिलाओं में आक्रोश व्याप्त है। लाभ से वंचित सैकड़ों की सं या में महिलाएं सोमवार को प्रखंड कार्यालय पहुंची।महिलाओं ने कहा कि आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया। प्रखंड कार्यालय में सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतारें लगी रहीं।

कई महिलाओं ने शिकायत की कि अधिकारियों द्वारा बार.बार नए दस्तावेज की मांग की जा रही हैए जबकि वे पहले ही सभी आवश्यक कागजात जमा कर चुकी हैं।

महिलाओं का कहना है कि सरकार एक ओर महिला सशक्तिकरण की बात करती है। वहीं दूसरी ओर योजनाओं में ऐसी जटिलताएं रखी जाती हैं कि आम महिलाओं को इसका लाभ आसानी से नहीं मिल पाता।इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिषेक पांडेय ने कहा कि कुछ महिलाओं के दस्तावेजों में त्रुटि होने के कारण उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सका।हालांकिए उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी योग्य लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा और प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।गढ़वा में भी महिलाएं परेशान उधरए गढ़वा में भी महिलाएं काफी परेशान हैं। सोमवार को खरौंधी पंचायत से शिल्पा देवी, विमला देवी इंदा देवी, अंजिला देवी, सुंडी पंचायत से शारदा देवी, सुषमा देवी, चिंता देवी, सोमरी देवीए अनीता देवी, कूपा पंचायत से रीना देवी, तेतरी देवी, पुष्पा देवी, अनीता देवी, चंदा देवी, चंदनी पंचायत से सुकरी देवी, हेमंती देवी, कलावती देवी प्रखंड कार्यालय पहुंची थी।

गैंगस्टर अमन साहू का भाई भी कुख्यात क्रिमिनल, आतंकवादियों से कनेक्शन के गंभीर आरोप

रांची १७/११ (संवाददाता):पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुए अपराधी अमन साहू के श्राद्धकर्म में जेल में बंद उसका भाई आकाश कुमार नहीं जा सकेगा। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने सोमवार को उसकी ओर से श्राद्धकर्म में शामिल होने के लेकर दाखिल औपबंधिक जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।

अमन साहू के मारे जाने के बाद 11 मार्च को भाई के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए उसने 13 दिनों की औपबंधिक जमानत की मांग की थी। आकाश साहू वर्तमान में एनआईए से जुड़े मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में है।

एनआइए ने उसे छह अगस्त 2024 को गिर तार किया था। उसपर टेरर फंडिंग के पैसे से फार्च्यूनर कार खरीदने का आरोप है। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर पेशी के लिए रायपुर से रांची लाया जा रहे अमन साहू को पलामू के चैनपुर

थाना क्षेत्र में एनकाउंटर कर ढेर कर दिया गया। बता दें कि अमन साहू का शुरुआती जीवन पतरातू में बीता था। अमन तीन भाइयो में दूसरे नंबर पर था। अमन ने पतरातू से ही इंटर की पढ़ाई की थी। अमन के दादा हरिदास साव मतवे में खेती.बाड़ी करते थे। बड़ा भाई गोलू इंजीनियर है जबकि छोटा भाई आकाश टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में है। शुरुआती दिनों में अमन साव इंटर करने के बाद पतरातु में मोबाइल दुकान खोला जहां दुकानदारी के दौरान वह सुशील श्रीवास्तव गिरोह के संपर्क में आया। शुरू से बड़े सपने देखने वाला अमन साव कु यात सुशील श्रीवास्तव गिरोह के लिए काम करते करते क्षेत्र में अपना पकड़ बना लिया। इसके बाद अपना गिरोह बनाकर काम करने लगा। सुशील श्रीवास्तव और भोला पांडेय गिरोह की दबिश बढ़ने पर अमन पूरे परिवार के साथ मतवे आ गया। मतवे में भी अमन के पिता ने किराने की दुकान खोल ली। अमन का नानी घर बुंडू में है। वहीं अमन साहू के एनकाउंटर के बाद 22 घंटे तक परिवार का कोई सदस्य उसका शव लाने नहीं गया था। हालांकिए बाद में उसका चचेरा भाई शव लेने पहुंचा था। पोस्टमार्टम के बाद उसे अमन साहू का शव सौंप दिया गया था।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

आरएसपी में आगामी सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025 के उपलक्ष्य में विक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक संवाद सत्र आयोजित

राउरकेला १७/११ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के सामग्री प्रबंधन विभाग के स मेलन कक्ष में आगामी सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025 के उपलक्ष्य में विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया गया। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), श्री अनिल कुमार ने इस सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मु य महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन), श्री टी. विनोद, मु य महाप्रबंधक (अनुरक्षण), श्री एस एस रॉयचौधरी, मु य महाप्रबंधक (सीसीडब्ल्यू), श्री आलोक कुमार बेहरा, मु य महाप्रबंधक (यांत्रिक), श्री डी के पालो, मु य महाप्रबंधक (सतर्कता एवं एसीवीओ) और सामग्री प्रबंधन एवं सतर्कता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिला लघु उद्योग संघ (डीएसएसआईए), ओडिशा युवा उद्यमी संघ (ओवाईईए), ओडिशा लघु एवं मध्यम उद्यम संघ (ओएएसएमई) और राउरकेला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (आरसीसीआई) के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री अनिल कुमार ने सतर्कता विभाग और सामग्री प्रबंधन कर्मीसमूह द्वारा ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयासों की सराहना की, जो व्यावसायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष प्रथाओं को मजबूत करते हैं। उन्होंने सभी हितधारकों से नैतिक आचरण और सामूहिक जि मेदारी के मूल्यों को बनाए रखने का भी आग्रह किया।

महाप्रबंधक (सतर्कता) एवं एसीवीओ, श्री रंजन भारती ने सभी प्रतिभागियों को सतर्कता सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई और पारदर्शिता और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने में विक्रेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला और इस पहल में बाहरी हितधारकों को शामिल करने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इससे पहले, श्री टी. विनोद ने विक्रेताओं का स्वागत किया और कार्यक्रम का अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें इस वर्ष के विषय, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पालन के बारे में विवरण शामिल था।

उप प्रबंधक (विपणन), श्री एम सी कुमार ने विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, जेम (त्द्गरू) के माध्यम से खरीद और एसआरएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से निविदा प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श सत्र में विक्रेताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और निविदा, खरीद और विक्रेता प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। महाप्रबंधक (विपणन), श्री जी एस गोस्वामी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ प्रबंधक (विपणन), सुश्री स्नेहा जी महंती ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया।

एमसीएल की सीएसआर निधि से तालचेर में स्थापित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कक्षाओं की शुरुआत

पवित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, तालचेर में एमबीबीएस क्लास का शुभारंभ

तालचेर/संबलपुर १७/११ (संवाददाता):पबित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, तालचेर में आज आधिकारिक रूप से एमबीबीएस कक्षाओं का शुभारंभ हुआ। यह संस्थान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत स्थापित किया गया है। इस शुरुआत ने क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह मेडिकल कॉलेज एमसीएल की सुलभ, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और अपने कमांड क्षेत्रों में उच्च चिकित्सा सेवा शिक्षा के अवसरों के विस्तार के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पहले बैच के एमबीबीएस छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए, एमसीएल ने उन्हें समर्पण, करुणा और समाज की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ अपनी मेडिकल यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उद्घाटन समारोह में श्री समीर कुमार जेना, उपगिलादिस जिलाधीश, तालचेर; श्री अशोक कुमार धल, एरिया जनरल मैनेजर, जगन्नाथ एरिया; तथा श्री मदन मोहन प्रधान, सीडीएमओ उपस्थित थे। वरिष्ठ अधिकारी, फैकल्टी सदस्य, तथा शैक्षणिक और चिकित्सकीय समुदाय के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहे, जिससे संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों के औपचारिक आरंभ किया गया। एमबीबीएस कार्यक्रम की शुरुआत से क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उ मीद है, जिससे सक्षम चिकित्सा पेशेवरों का निर्माण होगा और समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया जा सकेगा।

एकता पदयात्रा के लिए एकजुट हुआ

भुवनेश्वर १७/११ (संवाददाता):ओडिशा ने गुरुवार को बालासोर के नीलगिरि में एकता पदयात्रा का शुभारंभ करके भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के राष्ट्रव्यापी उत्सव में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मु यमंत्री मोहन चरण माझी ने किया, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देते हुए पदयात्रा का नेतृत्व किया। नीलगिरि से मित्रपुर तक 9 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में हजारों छात्रों, युवाओं, नागरिकों और सरकारी अधिकारियों ने एकता और देशभक्ति का संदेश देते हुए भाग लिया। छात्रों ने एकजुटता की भावना का प्रतीक 100 फुट लंबा तिरंगा गर्व से थाम रखा था। पदयात्रा से पहले, मु यमंत्री ने नीलगिरि के जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और पुलिस ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम में बालासोर की भूमिका और सरदार पटेल का जीवन पर एक फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए, मु यमंत्री ने कहा कि एकता पदयात्रा केवल एक पदयात्रा नहीं, बल्कि भारतीयता का प्रतीक है, जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य को दर्शाती है। आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, नीलगिरी, वह सिर्फ़ एक भौगोलिक जगह नहीं है; यह लोगों की शक्ति और लोकतंत्र की धड़कन है, उन्होंने ऐतिहासिक नीलगिरी जन आंदोलन को ओडिशा के स्वतंत्रता संग्राम के एक चमकदार अध्याय के रूप में याद करते हुए कहा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह आंदोलन शोषण और अन्याय के ख़िलाफ़ स्थानीय युवाओं, किसानों, मज़दूरों और शिक्षित नागरिकों की एकता का प्रतिनिधित्व करता है. एक सामूहिक आवाज़ जो अधिकारों, स मान और स्वाभिमान के लिए खड़ी थी। अतीत और वर्तमान के बीच समानता दर्शाते हुए, माझी ने कहा,आज का मार्च विविधता में एकता का यही संदेश देता है। जाति, धर्म या भाषा से परे, हम सभी भारतीय हैं। यह एकता हमारी ताकत और हमारी पहचान है। मु यमंत्री ने रोज़गार, शिक्षा, खेल और रचनात्मकता में पहल के ज़रिए युवा सशक्तीकरण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार स्तंभों किसान, ग़रीब, महिलाएँ और युवा पर आधारित विज़न से प्रेरित है।

ओडिशा ईवी नीति 2.0 लाने के लिए तैयार

भुवनेश्वर १७/११ (संवाददाता): विकासशील ओडिशा 2036 के दृष्टिकोण के अनुरूप, राज्य यहाँ शहर में एक हितधारक परामर्श बैठक के बाद अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 को अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस संशोधित नीति का उद्देश्य स्वच्छ और हरित गतिशीलता में अग्रणी के रूप में राज्य की स्थिति को मजबूत करना है। वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की प्रधान सचिव उषा पाधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अंतर-विभागीय समन्वय और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर बल दिया गया। बैठक में ओडिशा ईवी नीति 2.0 को अंतिम रूप देने के लिए ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा गया। पाधी ने राज्य भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक सुचारू और समावेशी बदलाव सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण और नीतिगत संरेखण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। परिवहन, आवास एवं शहरी विकास, ऊर्जा, वित्त, और कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने चर्चा में भाग लिया। प्रमुख उपस्थित लोगों में परिवहन आयुक्त अमिताव ठाकुर, ओएसआरटीसी के सीएमडी एनबीपीएस राजपूत और सीआरयूटी के एमडी संजय बिस्वाल शामिल थे।

प्रतिभागियों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया, जिनमें बढ़ी हुई खरीद प्रोत्साहन, वाहन रेट्रोफिटिंग और स्क्रैपेज लाभ, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास और ओडिशा में ईवी पहल की दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन करने के लिए एक समर्पित राज्य ईवी फंड का निर्माण शामिल है।

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया

कटक १७/११ (संवाददाता): उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य पर्यटन विभाग को बालासोर जिले में चौमुख-दगरा समुद्र तट के विकास कार्य में तेजी लाने और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। मु य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति एमएस रमन की खंडपीठ ने मंगलवार को एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किया, जिसमें राज्य सरकार को समुद्र तट पर पर्यटन अवसंरचना विकसित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। बालासोर के बलियापाल निवासी अनोज कुमार महापात्रा और राजेश चौधरी ने इस स्थल पर लंबे समय से लंबित पर्यटन परियोजना के कार्यान्वयन की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की थी।

याचिका के अनुसार, पर्यटन विभाग ने 1998 में ही चौमुख-दगरा समुद्र तट को एक संभावित पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना था। याचिका में तर्क दिया गया है कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और नदियों से निकटता के कारण यह स्थल राज्य की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है और स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार कर सकता है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में एक वर्षीय प्रशिक्षण के लिए 319 स्नातक तथा डिप्लोमा शिक्षुता प्रशिक्षु शामिल

राउरकेला १७/११ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) में प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961/1973 के प्रावधानों के तहत एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 319 स्नातक और डिप्लोमा प्रशिक्षुता प्रशिक्षुओं के प्रथम बैच को शामिल किया गया है। प्रशिक्षुओं के लिए एक परिचय कार्यशाला गोपबंधु सभागार में शुरू हुई। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता मु य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), श्री मानस रंजन रथ ने की। मंच पर मु य महाप्रबंधक (मानव संसाधन-एलएंडडी), श्री पी के साहू भी उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए, श्री रथ ने राष्ट्र निर्माण में आरएसपी की महत्वपूर्ण भूमिका और भारत सरकार की कौशल भारत पहल में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रशिक्षुओं से अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने और अपने रोजगार कौशल विकसित करने के अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। श्री साहू ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दायरे और संरचना पर विस्तार से प्रकाश डाला और प्रतिभागियों को सीखने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अभिमुखीकरण कार्यक्रम के दौरान, प्रशिक्षुओं को सेल और आरएसपी, सुरक्षा पहलुओं, गैस सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुझावों के साथ-साथ कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण एकीकृत इस्पात निर्माण प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। सत्रों के दौरान ऑडियो-विजुअल भी दिखाए जाएँगे। कार्यक्रम का समन्वयन उप महाप्रबंधक (ज्ञानार्जन एवं विकास), श्री के के जायसवाल द्वारा किया गया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के कौशल भारत मिशन के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करके, आरएसपी का उद्देश्य युवाओं को उनके चुने हुए व्यवसायों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और विशेषज्ञता से लैस करना है।

सर्दी का सितम, दरिंगबाड़ी में तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज

भुवनेश्वर १७/११ (संवाददाता): भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को ओडिशा में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और कंधमाल जिले के दारिंगबाड़ी में सबसे कम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक बुलेटिन में बताया गया है कि पूर्वी राज्य में कम से कम 17 स्थानों पर गुरुवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

कंधमाल जिले के एक अन्य शहर फूलबनी में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि झारसुगुड़ा में 10.9 डिग्री सेल्सियस, राउरकेला में 11.1 डिग्री सेल्सियस और भवानीपटना में 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुलेटिन में कहा गया है कि अगले तीन दिनों में पारे के स्तर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बुलेटिन में बताया गया है कि राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में 14.1 डिग्री सेल्सियस और निकटवर्ती कटक में 14.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।